प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक–17.10.2023 (सं0–341)

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना, के द्वारा आर्थिक एवं साइबर अपराधों के रोथाम हेतु की जा रही कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना, आर्थिक एवं साइबर अपराधों के रोकथाम एवं साइबर सम्बन्धित मामलों के अनुश्रवण हेतु बिहार पुलिस की राज्य स्तरीय नोडल संस्था एवं विशिष्ट इकाई है। साइबर अपराध के काण्डों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, साइबर जागरुकता का प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कराने आदि से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन इकाई के द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार के वर्ष 2011 में गठन के पश्चात साइबर से सम्बन्धित मामलों को देखने एवं अनुश्रवण हेतु साइबर सेल का गठन किया गया था जो एक छोटे स्वरूप में स्थापित था। वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के केन्द्रीय प्रायोजित Cyber Crime Prevention Against Women & Children (CCPWC) योजना आने के पश्चात साइबर सेल के विस्तार हेतु राज्य साइबर फॉरेन्सिक सह प्रशिक्षण लैब की स्थापना करने एवं क्षमता सम्वर्धन (प्रशिक्षण) हेतु क्रमशः 2.30 करोड़ एवं 6530000/– रु0 आवंटित किये गयें।

उपरोक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य साइबर फॉरेन्सिक सह प्रशिक्षण लैब स्थापित किया जा चुका है जो जून 2022 से कार्यरत है। फॉरेन्सिक लैब हेतु उच्च गुणवत्ता के 06 हार्डवेयर एवं 12 सॉफ्टवेयर खरीद किये गये हैं जिसमें हाई इंड वर्क स्टेशन भी शामिल हैं। फॉरेन्सिक लैब की मदद से अभी तक 92 मोबाइल, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, डी0वी0आर0 आदि का Data extraction कर विभिन्न कांडों के अनुसंधान में सहयोग किया गया।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक–एक साइबर लैब खोलने की योजना है। इसके प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक रेन्ज में क्षेत्रीय स्तर पर फॉरेन्सिक लैब स्थापित करने की तैयारी चल रही है ताकि साइबर सम्बन्धित कांडों में तकनीकी अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम एवं सुलभ बनाया जा सके।

साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल के हेल्पलाईन नं0–1930 कॉल सेन्टर के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 44 लाख रु0 का आवंटन किया गया है, जिससे 30 डेस्कटॉप कम्प्यूटर सेट, सर्वर एवं क्लाउड टेलीफोनिक सिस्टम की खरीद की जा रही है।

साइबर से सम्बन्धित मामलों में सहयोग हेतु IIT PATNA, C-DAC PATNA एवं अन्य NGO से आवश्यक collaboration किया जा रहा है, जिसमें MOU की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु Drone, Satellite Phones आदि की खरीद की जा रही है। State forensic cum Cyber Training Lab के सुदृढ़ीकरण हेतु Advance Version Tools खरीदने की कार्य योजना बनायी जा रही है, जिसमे High End Mobile Phones Unlock करना, Cryptocurrency को blockchain पर Trace करना इत्यादि शामिल हैं।

Dark Net पर अवैध रूप से व्यापार एवं गैरकानूनी कार्यों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से Dark Net Lab की स्थापना करने की अग्रिम योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक रूप से Patrolling एवं Monitoring करने की कार्रवाई की जायेगी।

xxxxxxxx